पटना में दिनांक–24 जून, 2026 बुधवार को अपराह्न 5:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

उच्च शिक्षा विभाग

1. प्रायोजक निकाय मिल्ली ट्रस्ट, गली नं०–01, आरामनगर, कुतुब रोड, पहाड़गंज, नई दिल्ली (शाखा कार्यालय स्टेडियम रोड, मधुबनी, बिहार) को निजी क्षेत्र में शांजा विश्वविद्यालय, मधुबनी की स्थापना एवं विश्वविद्यालय संचालन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 1. स्वीकृत।

उच्च शिक्षा विभाग

2. प्रायोजक निकाय अम्बेदकर इंस्टीच्यूट ऑफ हायर एजुकेशन ट्रस्ट, छितनावाँ, दानापुर, पटना–801503 को निजी क्षेत्र में वी०वी० गिरी विश्वविद्यालय, दरौंधा, सीवान की स्थापना एवं विश्वविद्यालय संचालन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 2. स्वीकृत।

उच्च शिक्षा विभाग

3. प्रायोजक निकाय एस०ए० फाउंडेशन, श्री कृष्णापुरी, न्यू एरिया, नवादा (पो०+थाना+जिला–नवादा, पिन–805110) को निजी क्षेत्र में एस०ए० विश्वविद्यालय, अशोक नगर, नवादा, बिहार की स्थापना एवं विश्वविद्यालय संचालन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 3. स्वीकृत।

उच्च शिक्षा विभाग

4. प्रायोजक निकाय हिमालय एजुकेशनल ट्रस्ट, लोहियानगर, कंकड़बाग, पटना को निजी क्षेत्र में हिमालय विश्वविद्यालय, पालीगंज, पटना की स्थापना एवं विश्वविद्यालय संचालन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 4. स्वीकृत।

उच्च शिक्षा विभाग

5. प्रायोजक निकाय सीतयोग एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी, जी–1, कुंती विला अपार्टमेंट, (पूनम गैस गोदाम के नजदीक) अंबेदकर पथ, खाजपुरा, पटना को निजी क्षेत्र में सीतयोग विश्वविद्यालय, जसोईया मोड़, औरंगाबाद, बिहार की स्थापना एवं विश्वविद्यालय संचालन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 5. स्वीकृत।

कृषि विभाग

6. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित परम्परागत कृषि विकास योजना (60:40) के लिए वित्तीय वर्ष 2026–27 में 3060.00 लाख (तीस करोड़ साठ लाख) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — 6. स्वीकृत।

कृषि विभाग

7. चतुर्थ कृषि रोड मैप के अन्तर्गत तेलहनी फसलों को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में राष्ट्रीय खाद्य तेल–तेलहन मिशन अन्तर्गत कुल 3618.62700 लाख (छत्तीस करोड़ अठारह लाख बासठ हजार सात सौ) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। 7. स्वीकृत।

कृषि विभाग

8. चतुर्थ कृषि रोड मैप (डी०पी०आर०) अंतर्गत कृषोन्नति योजना के तहत एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना (आत्मा योजना) (60:40) के कार्यान्वयन के लिये बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती), पटना तथा जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) को वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए कुल 14899.314 लाख (एक सौ अड़तालीस करोड़ निन्यानवे लाख एकतीस हजार चार सौ) रूपये मात्र की लागत पर योजना का कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। 8. स्वीकृत।

कला एवं संस्कृति विभाग

9. संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार से संबद्ध संस्थान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली एवं पुरातत्व निदेशालय, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना के बीच "प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958" के तहत घोषित राष्ट्रीय महत्व के पुरातात्विक स्थलों/स्मारकों के जीर्णोद्धार, उन्नयन एवं रख–रखाव कार्य हेतु समझौता ज्ञापन (MOU) किये जाने के संबंध में। 9. स्वीकृत।

वित्त विभाग

10. बिहार यात्रा–भत्ता नियमावली, 1949 के नियम–69(2) को विलोपित किये जाने के संबंध में। 10. स्वीकृत।

ग्रामीण विकास विभाग

11. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के वित्तीय वर्ष 2025–2026 एवं 2026–2027 तक के कुल व्यय की स्वीकृत सीमा के अन्तर्गत हुए अवधि विस्तार के सापेक्ष लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान (LSBA)–द्वितीय चरण की समयावधि को 2025–2026 एवं 2026–2027 तक के लिये विस्तारित किये जाने के साथ लोहिया स्वच्छता योजना अंतर्गत अतिरिक्त 2467.00 लाख (चौबीस करोड़ सड़सठ लाख) की स्वीकृति के संबंध में। 11. स्वीकृत।

ग्रामीण विकास विभाग

12. महात्मा गॉधी नरेगा अधिनियम की धारा 12 (1) में निहित प्रावधानों के तहत गठित बिहार ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् को निरसित करते हुए विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत–जी राम जी) अधिनियम, 2025 की धारा–13 (1) के प्रावधान के अनुरूप विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत–जी राम जी) योजना, बिहार, 2026 की कंडिका–8 में निहित प्रावधान के आलोक में राज्य अंतर्गत बिहार राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् के गठन की स्वीकृति के संबंध में। — **12. स्वीकृत।**

ग्रामीण विकास विभाग

13. विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत–जी राम जी) योजना, बिहार, 2026 की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की शक्ति के प्रत्यायोजन के संबंध में। — **13. स्वीकृत।**

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
(मत्स्य निदेशालय)

14. डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग (मत्स्य निदेशालय) नियंत्रणाधीन कनीय अभियंता (मूल कोटि) के कुल 40 पदों का चिन्हितीकरण एवं पुनर्गठन करने की स्वीकृति के संबंध में। — **14. स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

15. केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) अंतर्गत छपरा सिवरेज नेटवर्क परियोजना हेतु लागत राशि रू० 76,48,90,752/–(छिहत्तर करोड़ अड़तालीस लाख नब्बे हजार सात सौ बावन रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। — **15. स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

16. अर्बन चैलेंज फंड (यू०सी०एफ०) मिशन में भागीदारी हेतु आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं नगर निकायों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने की स्वीकृति के संबंध में। — **16. स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

17. बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 (यथासंशोधित) में संशोधन करते हुए प्रमंडलीय आयुक्त को आयोजना क्षेत्र प्राधिकार के पदेन अध्यक्ष तथा जिला पदाधिकारी को पदेन उपाध्यक्ष नामित करने की स्वीकृति के संबंध में। — **17. स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

18. राज्य में सुनियोजित शहरी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बारहवें ग्रीनफील्ड सैटेलाईट टाउनशिप के रूप में रोहतास जिला अन्तर्गत डेहरी में ग्रीनफील्ड सैटेलाईट टाउनशिप का क्षेत्र एवं विकास प्रक्रिया के चयन की स्वीकृति के संबंध में। — **18. स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

19. "छपरा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर आयोजना क्षेत्र" के क्षेत्र विस्तार की स्वीकृति के संबंध में। — **19. स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

20. इंडिपेंडेन्ट थर्ड पार्टी ब्रिज सेफ्टी ऑडिट कराने हेतु कुल 4776.05 लाख (सैंतालीस करोड़ छिहत्तर लाख पाँच हजार) मात्र रूपये के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — **20. स्वीकृत।**

पर्यटन विभाग

21. मुंगेर जिलान्तर्गत तारापुर में सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय सुविधाएं विकसित करने हेतु मौजा–गाजीपुर, थाना सं०–191, जमाबंदी संख्या–289 की 15 एकड़ 01 डिसमिल (पन्द्रह एकड़ शून्य एक डिसमिल) भूमि को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–644 दिनांक–15.06.1999 की कंडिका–05 एवं बिहार खासमहाल नीति, 2011 की कंडिका–1 एवं कंडिका–4(ङ) में अंकित प्रावधान को शिथिल करते हुए ईशा फाउण्डेशन, ईशा योग केन्द्र, वेल्लियांगिरी फुटहिल, कोयंबटूर, तामिलनाडु को 1 रूपये के टोकन मूल्य पर 99 वर्ष के लिए लीज बंदोबस्त किये जाने एवं तदालोक में किये जाने वाले समझौता ज्ञापन प्रारूप (MOU) की स्वीकृति के संबंध में। — **21. स्वीकृत।**

विधि विभाग

22. केन्द्र प्रायोजित स्कीम अन्तर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, महराजगंज (सिवान) में प्रस्तावित 10 कोर्ट भवन (G+5), एमिनिटी भवन (G+4) एवं हाजत भवन (G+1) के निर्माण कार्य हेतु रू०–34,33,26,000/–(चौंतीस करोड़ तैंतीस लाख छब्बीस हजार रूपये) की प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति। — **22. स्वीकृत।**

विधि विभाग

23. केन्द्र प्रायोजित स्कीम अन्तर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के परिसर में 20 कोर्ट भवन (G+5) के निर्माण कार्य हेतु रू०–53,02,26,000/–(तिरेपन करोड़ दो लाख छब्बीस हजार रूपये) की प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति। — **23. स्वीकृत।**

विधि विभाग

24. केन्द्र प्रायोजित स्कीम अन्तर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, बेगूसराय के परित्यक्त एस०डी०जे०एम० कोर्ट के भू–खण्ड पर प्रस्तावित 15 कोर्ट भवन (G+7) के निर्माण कार्य हेतु रू०–39,04,13,000/– (उनचालीस करोड़ चार लाख तेरह हजार रूपये) की प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति। — 24. **स्वीकृत।**

विधि विभाग

25. केन्द्र प्रायोजित स्कीम अन्तर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, रजौली (नवादा) में 10 कोर्ट भवन (G+5), एमिनिटी भवन (G+4) एवं हाजत भवन (G+1) के निर्माण कार्य हेतु रू०–38,38,31,000/–(अड़तीस करोड़ अड़तीस लाख इकतीस हजार रूपये) की प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति। — 25. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

26. श्रीमती अंजली कुमारी आनंद, तत्कालीन सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना सम्प्रति निलंबित को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–14 (XI) के तहत "सरकारी सेवा से बर्खास्तगी", जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी, का दण्ड अधिरोपित करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 26. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

27. गया जिलान्तर्गत बोधगया अंचल के मौजा–बोधगया, थाना सं०–359, खाता सं०–1021 (नया), खेसरा सं०–3117 (नया), रकवा–34 डी० बिहार सरकार के स्वामित्व की भूमि कतिपय शर्तों के अधीन नामग्याल तांत्रिक कॉलेज (Personal Monastery H.H. of the Dalai Lama) को 50 वर्षों के लिए लीज बंदोबस्ती करने की स्वीकृति के संबंध में। — 27. **स्वीकृत।**

सूचना प्रावैधिकी विभाग

28. राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारिस्थितिकी तंत्र के विकास हेतु माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित करने की स्वीकृति। — 28. **स्वीकृत।**

सूचना प्रावैधिकी विभाग

29. राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारिस्थितिकी तंत्र के विकास हेतु को–रोवर (CoRover) प्राइवेट लिमिटेड एवं सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित करने की स्वीकृति। — 29. **स्वीकृत।**

सूचना प्रावैधिकी विभाग

30. राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारिस्थितिकी तंत्र के विकास हेतु एक्सोनवाइज प्राइवेट लिमिटेड (Sarvam) एवं सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित करने की स्वीकृति। — 30. स्वीकृत।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

31. राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारिस्थितिकी तंत्र के विकास हेतु गूगल क्लाउड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Google Cloud India Pvt. Ltd.) एवं सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित करने की स्वीकृति। — 31. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

32. वित्तीय वर्ष 2026–27 में केन्द्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN) योजनान्तर्गत राज्य के PVTGs के लिए 06 जिलों में कुल 15 छात्रावास के निर्माण एवं संचालन हेतु केन्द्रांश की राशि कुल ₹24,75,00,000/–(चौबीस करोड़ पचहत्तर लाख) रूपये मात्र एवं राज्यांश की राशि कुल ₹16,50,00,000/–(सोलह करोड़ पचास लाख) रूपये मात्र अर्थात कुल ₹41,25,00,000/–(एकतालीस करोड़ पच्चीस लाख) रूपये की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — 32. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

33. वित्तीय वर्ष 2026–27 में केन्द्र प्रायोजित योजना धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) योजनान्तर्गत राज्य के 08 जिलों में कुल 19 छात्रावासों के निर्माण एवं संचालन हेतु केन्द्रांश की राशि कुल ₹36,25,00,000/– (छत्तीस करोड़ पच्चीस लाख) रूपये मात्र एवं राज्यांश की राशि कुल ₹24,16,99,000/– (चौबीस करोड़ सोलह लाख निन्यानवे हजार) रूपये मात्र अर्थात कुल ₹60,42,00,000/– (साठ करोड़ बयालिस लाख) रूपये की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — 33. स्वीकृत।

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

34. "औद्योगिक संबंध (बिहार) नियमावली, 2026" की स्वीकृति के संबंध में। — 34. स्वीकृत।

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

35. "सामाजिक सुरक्षा (बिहार) नियमावली, 2026" की स्वीकृति के संबंध में। — 35. स्वीकृत।

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

36.	"उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा (बिहार) नियमावली, 2026" की स्वीकृति के संबंध में।	**36.**	**स्वीकृत।**

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

37.	"मजदूरी संहिता (बिहार) नियमावली, 2026" की स्वीकृति के संबंध में।	**37.**	**स्वीकृत।**

पर्यटन विभाग

38.	पटना जिला के मोकामा शहर में सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय सुविधाएं विकसित करने हेतु मौजा–मोकामा खास, थाना सं०–30 की 10.11 एकड़ (दस एकड़ ग्यारह डिसमिल) भूमि को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–644 दिनांक–15.06.1999 की कंडिका–05 एवं बिहार खासमहाल नीति, 2011 की कंडिका–1 एवं कंडिका–4(ड़) में अंकित प्रावधान को शिथिल करते हुए तिरूमला तिरूपति देवस्थानम्, तिरूपति, आंध्र प्रदेश को 1 रूपये के टोकन मूल्य पर 99 वर्ष के लिए लीज बंदोबस्त किये जाने एवं तदालोक में किये जाने वाले समझौता ज्ञापन प्रारूप (MOU) की स्वीकृति के संबंध में।	**38.**	**स्वीकृत।**

गन्ना उद्योग विभाग

39.	बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति–2026 की स्वीकृति।	**39.**	**स्वीकृत।**

गृह विभाग
(कारा)

40.	बिहार कक्षपाल संवर्ग नियमावली, 2014 को संशोधित कर बिहार कक्षपाल संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2026 के गठन के संबंध में।	**40.**	**स्वीकृत।**

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

41.	राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना के लिए सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का 01 (एक) अतिरिक्त पद सृजित करने के संबंध में।	**41.**	**स्वीकृत।**
42.	बिहार में पर्यटकीय आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु हुडको (HUDCO-Housing and Urban Development Corporation) एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से कतिपय शर्त्तों एवं राज्य सरकार की गारंटी पर 5,000 करोड़ (पाँच हजार करोड़) रूपये वित्त पोषण प्राप्त करने हेतु बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को प्राधिकृत करने की स्वीकृति के संबंध में।	**42.**	**स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

43. राज्य में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास हेतु ₹1,00,000 करोड़ (एक लाख करोड़ रूपये) का दीर्घकालिक वित्त पोषण प्राप्त करने के लिए हुडको के साथ मेमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग (MoU) हस्ताक्षरित करने की स्वीकृति के संबंध में। — **43. स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

46. राज्य के प्रारंभिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापक के स्थानान्तरण को विनियमित करने हेतु "बिहार राज्य शिक्षक स्थानान्तरण नियमावली, 2026" की स्वीकृति के संबंध में। — **46. स्वीकृत।**

अन्यान्य

47. दिनांक–17.06.2026 को भोजपुर जिला के शाहपुर थाना अंतर्गत बिलौटी ग्राम में हुए पुलिस कार्रवाई की घटना की न्यायिक जाँच हेतु विभागीय अधिसूचना –7146, दिनांक–24.06.2026 द्वारा माननीय न्यायमूर्ति, श्री विनोद कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में गठित न्यायिक जाँच आयोग एवं आयोग के लिए विचारणीय बिंदु (Terms of Reference) पर मंत्रिपरिषद् द्वारा घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी।